

Indian Journal of Commerce, Business & Management (IJCBM)



A Peer Reviewed Research journal of Commerce, Business & Management

ISSN : 3108-057X (Online)

3108-1282 (Print)

Vol.-1; Issue-2 (Oct.-Dec.) 2025

Page No.- 120-130

©2025 IJCBM

<https://ijcbm.gyanvidya.com>

Author's :

Dr. Anil Kumar

Senior Assistant Professor,
P.G. Department of Economics,
BNMU West Campus, P.G. Centre
Saharsa.

Corresponding Author :

Dr. Anil Kumar

Senior Assistant Professor,
P.G. Department of Economics,
BNMU West Campus, P.G. Centre
Saharsa.

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की वैश्विक बिसात पर भारत : अवसर, चुनौतियाँ और रणनीतिक दिशा

सारांश : वर्ष 2025 तक, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध एक स्थायी भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में रूपांतरित हो चुका है, जो वैश्विक व्यवस्था को मौलिक रूप से बदल रहा है। यह शोध पत्र इस नए वैश्विक परिदृश्य का भारत के दृष्टिकोण से एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और यह तर्क देता है कि यह टकराव भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो रणनीतिक अवसर और गंभीर कमजोरियों का एक जटिल अंतर्संबंध प्रस्तुत करता है। एक ओर, "चाइना प्लस वन" जैसी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण रणनीतियों और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी सक्रिय घरेलू नीतियों ने भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया है।

हालांकि, यह पत्र यह भी रेखांकित करता है कि इन अवसरों का लाभ उठाना सशर्त है। भारत की महत्वाकांक्षाएँ दवा सामग्री (APIs) और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में चीन पर गहरी आयात निर्भरता, वैश्विक आर्थिक मंदी के खतरे, और वियतनाम तथा मेक्सिको जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से मिल रही कड़ी चुनौती से बाधित होती हैं। भू-राजनीतिक रूप से, भारत ने "बहु-संरक्षण" की एक कुशल रणनीति के माध्यम से इस तनाव को प्रबंधित किया है, जिसमें वह क्वाड (QUAD) जैसे समूहों के माध्यम से अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को गहरा कर रहा है, साथ ही चीन के साथ अपने जटिल संबंधों को भी प्रबंधित कर रहा है।

अंततः, यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अमेरिका-चीन संघर्ष ने भारत के लिए वैश्विक मंच पर एक अग्रणी भूमिका निभाने का द्वार तो खोल दिया है, लेकिन इस क्षमता को वास्तविकता में बदलना

पूरी तरह से भारत की अपनी आंतरिक सुधारों को लागू करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अतः, यह वैश्विक टकराव भारत के लिए एक बाहरी अवसर से कहीं अधिक, उसकी आंतरिक दृढ़ता और सुधार करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा है।

बीज शब्द : वैश्विक अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार, भू-राजनीतिक दृष्टिकोण एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला।

1. परिचय (Introduction) :

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में, वैश्विक व्यवस्था एक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है, जिसका केंद्र बिंदु संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.) और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के बीच बढ़ता हुआ रणनीतिक टकराव है। यह टकराव, जो 2018 में एक व्यापार युद्ध के रूप में सार्वजनिक चेतना में आया, अब मात्र टैरिफ और व्यापार घाटे के आर्थिक मुद्दों से कहीं आगे निकल चुका है। वर्ष 2025 तक आते-आते, यह एक बहुआयामी और गहरी वैचारिक प्रतिस्पर्धा में विकसित हो गया है, जिसके दायरे में प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण, सैन्य प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का भविष्य शामिल है। यह एक ऐसी भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (liberal international order) की नींव को चुनौती दे रही है, जिसे कुछ विद्वान "नई शीत युद्ध" (New Cold War) की संज्ञा भी दे रहे हैं (Mearsheimer, 2021)।

इस वैश्विक शक्ति संघर्ष के बीच, भारत एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थिति में है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, एक विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश और एक स्थापित लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ, भारत इस टकराव का एक मूक दर्शक मात्र नहीं है। इसके बजाय, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण खिलाड़ी (Pivotal Player) है जिसके रणनीतिक निर्णय न केवल इसके स्वयं के भविष्य को, बल्कि इस संघर्ष की दिशा और वैश्विक व्यवस्था के अंतिम स्वरूप को भी प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिकी और चीनी रणनीतिकारों के लिए, भारत एक महत्वपूर्ण "स्विंग स्टेट" (swing state) है, जिसे वे अपने खेमे में लाना चाहते हैं (Kissinger, 2014)। हालाँकि, भारत के लिए यह स्थिति गहन अवसरों और गंभीर चुनौतियों दोनों को एक साथ प्रस्तुत करती है, जो इसकी विदेश और आर्थिक नीतियों के लिए एक ऐतिहासिक परीक्षा है।

इस संघर्ष की शुरुआत अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीन पर लगाए गए गंभीर आरोपों से हुई थी, जिनमें अनुचित व्यापार प्रथाएं, बौद्धिक संपदा की बड़े पैमाने पर चोरी, प्रौद्योगिकी के जबरन हस्तांतरण और अमेरिकी बाजारों में चीनी सामानों की राज्य-प्रायोजित डंपिंग शामिल थी (United States Trade Representative [USTR], 2019)। चीन ने इन आरोपों को संरक्षणवादी बहाना बताते हुए जवाबी टैरिफ लगाए, और यह दुश्चक्र तेजी से बढ़ता गया। 2025 तक, यह स्पष्ट हो गया है कि यह केवल व्यापार संतुलन का मुद्दा नहीं है। अमेरिका का घोषित लक्ष्य अब चीन के तकनीकी उत्थान, विशेष रूप से 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में, को बाधित करना और वैश्विक मंच पर उसके बढ़ते प्रभाव को सीमित करना है (Center for Strategic and International Studies [CSIS], 2024)।

भारत के लिए, इस टकराव के निहितार्थ गहरे और बहुस्तरीय हैं। एक ओर, वैश्विक निगम अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के जोखिम को कम करने के लिए "चाइना प्लस वन" (China Plus One) रणनीति को सक्रिय रूप से अपना रहे हैं, जिससे भारत के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और अपने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को सफल बनाने का एक अभूतपूर्व अवसर पैदा हुआ है (World Bank, 2023)। दूसरी ओर, विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक विकास दर में गिरावट का खतरा मंडरा रहा है, जिसका

सीधा असर भारत के निर्यात और विकास की संभावनाओं पर पड़ सकता है (International Monetary Fund [IMF], 2025)। इसके अतिरिक्त, भारतीय उद्योग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ट्रिडिगेंड्स (APIs) और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के लिए चीनी आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो इसे आपूर्ति श्रृंखला के झटकों के प्रति संवेदनशील बनाता है। हाल के महीनों में, विशेष रूप से अगस्त 2025 में, अमेरिका द्वारा भारत सहित कई व्यापारिक भागीदारों पर लगाए गए नए टैरिफ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वाशिंगटन की संरक्षणवादी नीतियां केवल चीन तक सीमित नहीं हैं, जिसने नई दिल्ली के लिए समीकरण को और भी जटिल बना दिया है (Financial Times, August 30, 2025)।

यह शोध पत्र इसी जटिल और गतिशील परिदृश्य का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह उन आर्थिक अवसरों और चुनौतियों की गहन पड़ताल करेगा जिनका भारत सामना कर रहा है। साथ ही, यह उन भू-राजनीतिक मजबूरियों और रणनीतिक विकल्पों का मूल्यांकन करेगा जो भारत की विदेश नीति को आकार दे रहे हैं - जिसमें क्वाड (QUAD) जैसे समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के समूहों में इसकी बढ़ती भागीदारी से लेकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे मंचों पर चीन के साथ हालिया तनावपूर्ण संवाद तक शामिल है। इस पत्र का उद्देश्य इस मूल प्रश्न का उत्तर देना है: अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की इस नई वैश्विक बिसात पर, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करने, आर्थिक विकास को गति देने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए क्या मार्ग अपना सकता है?

2. भारत के लिए आर्थिक अवसर (Economic Opportunities for India) : अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध ने जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा की है, वहीं इसने भारत के लिए अप्रत्याशित आर्थिक अवसर भी उत्पन्न किए हैं। यह संघर्ष वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains - GVCs) में एक संरचनात्मक पुनर्संरचना को गति दे रहा है, जिसका लाभ उठाने के लिए भारत एक अद्वितीय स्थिति में है। इन अवसरों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विश्लेषित किया जा सकता है: आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थानांतरण, निर्यात में वृद्धि, और विदेशी निवेश का आकर्षण।

2.1 "चाइना प्लस वन" रणनीति और भारत एक विनिर्माण केंद्र के रूप में : व्यापार युद्ध और उसके बाद आई कोविड-19 महामारी ने बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) को एक केंद्रीकृत आपूर्ति श्रृंखला, विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भरता, के जोखिमों से अवगत कराया है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनियाँ अब "चाइना प्लस वन" (China Plus One) नामक एक **डी-रिस्किंग (de-risking)** रणनीति अपना रही हैं, जिसका उद्देश्य अपने उत्पादन का एक हिस्सा चीन से बाहर किसी अन्य देश में स्थानांतरित करना है (World Trade Organization, 2023)। इस रणनीति के लिए भारत एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभरा है। इसके कई कारण हैं:

- **विशाल घरेलू बाजार:** भारत का विशाल और बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार यहाँ निवेश करने वाली कंपनियों के लिए एक अंतर्निहित आकर्षण प्रदान करता है।
 - **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत के पास एक विशाल, युवा और अपेक्षाकृत सस्ती श्रम शक्ति है, जो इसे श्रम-गहन विनिर्माण के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।
 - **लोकतांत्रिक स्थिरता:** एक स्थिर, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली निवेशकों को नीतिगत पूर्वानुमान और कानून के शासन का भरोसा देती है, जो चीन के विपरीत है (The Economist Intelligence Unit, 2024)।
- इस प्रवृत्ति का सबसे स्पष्ट प्रभाव **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण**, विशेष रूप से स्मार्टफोन उत्पादन में देखा गया है। एप्पल (Apple) और सैमसंग (Samsung) जैसी वैश्विक कंपनियों ने भारत में अपने उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की

है। यह बदलाव भारत सरकार की **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive - PLI)** योजना से प्रेरित है, जिसने इन कंपनियों को भारत में अपनी आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है (Ministry of Electronics and Information Technology, 2025)। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा, स्पेशियलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, और टेक्सटाइल जैसे अन्य क्षेत्रों में भी निवेश और उत्पादन के स्थानांतरण की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।

2.2 निर्यात में वृद्धि की संभावना : अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में चीनी उत्पादों पर लगे उच्च टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों के लिए एक अवसर पैदा किया है। जिन उत्पाद श्रेणियों में चीन और भारत सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, वहाँ भारतीय माल अब तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि व्यापार युद्ध की शुरुआत के बाद से, अमेरिका के परिधान, ऑटो कंपोनेंट्स, और हल्के इंजीनियरिंग सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी घटी है, जबकि भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई है (Peterson Institute for International Economics, 2024)।

भारत सरकार भी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए, कपड़ा और परिधान क्षेत्र में, भारत गुणवत्ता और डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करके चीन द्वारा खाली किए गए उच्च-मूल्य वाले सेगमेंट को लक्षित कर रहा है। हालांकि, इस क्षेत्र में भारत को बांग्लादेश और वियतनाम से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिन्हें कई प्रमुख बाजारों में शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त है। इसलिए, निर्यात अवसरों को पूरी तरह से भुनाने के लिए भारत को न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि लॉजिस्टिक्स में सुधार और **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs)** पर सक्रिय रूप से बातचीत करने की भी आवश्यकता है (Federation of Indian Export Organisations, 2025)।

2.3 विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना : आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थानांतरण और निर्यात में वृद्धि, दोनों ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर बहुत अधिक निर्भर हैं। भारत ने हाल के वर्षों में FDI को आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती, श्रम कानूनों में सुधार, और **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)** रैंकिंग में सुधार के लिए उठाए गए कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। PLI योजना को 14 प्रमुख क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण का एक अभिन्न अंग बनाना है (NITI Aayog, 2024)।

इन प्रयासों के परिणाम FDI प्रवाह के आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। 2021-2024 की अवधि में, विनिर्माण क्षेत्र में FDI में लगातार वृद्धि देखी गई है, भले ही वैश्विक FDI प्रवाह में मंदी रही हो (Reserve Bank of India, 2025)। यह इंगित करता है कि निवेशक भारत को एक दीर्घकालिक निवेश गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। यह रुझान भारत के लिए न केवल पूंजी लाता है, बल्कि अपने साथ उन्नत तकनीक, प्रबंधन कौशल और वैश्विक बाजारों तक पहुंच भी लाता है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

3. भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियाँ (Economic Challenges for India) : जहाँ एक ओर अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध भारत के लिए नए अवसर पैदा करता है, वहीं यह अपने साथ गंभीर आर्थिक चुनौतियाँ और जोखिम भी लेकर आता है। इन चुनौतियों को नजरअंदाज करना भारत की आर्थिक रणनीति के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि इन जोखिमों का सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया, तो वे अवसरों से होने वाले लाभ को कम कर सकते हैं। प्रमुख आर्थिक चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

3.1 वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव : अमेरिका और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ होने के नाते,

वैश्विक विकास के प्रमुख इंजन हैं। इन दोनों के बीच एक लंबा और गहरा व्यापारिक टकराव वैश्विक व्यापार की मात्रा को कम करता है, निवेश में अनिश्चितता पैदा करता है, और समग्र वैश्विक मांग को कमजोर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने लगातार चेतावनी दी है कि यह संघर्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर पर एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है (International Monetary Fund [IMF], 2025)।

भारत के लिए इसका सीधा असर उसके निर्यात पर पड़ता है। भले ही भारत कुछ क्षेत्रों में चीन की बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ले, लेकिन यदि वैश्विक बाजार का कुल आकार ही सिकुड़ जाता है, तो समग्र निर्यात वृद्धि सीमित हो जाएगी। भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाएँ, कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और रत्न एवं आभूषण, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बाजारों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इन क्षेत्रों में मांग में कोई भी कमी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और रोजगार सृजन को धीमा कर देगी।

3.2 आयात पर निर्भरता और मूल्य वृद्धि का जोखिम : 'मेक इन इंडिया' की महत्वाकांक्षा के बावजूद, भारतीय उद्योग कई महत्वपूर्ण कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं (intermediate goods) और घटकों के लिए चीनी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। यह निर्भरता कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में विशेष रूप से चिंताजनक है:

- **फार्मास्यूटिकल्स:** भारत को "दुनिया की फार्मसी" के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह अपनी जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के लिए लगभग 70% तक सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients - APIs) का आयात चीन से करता है (Confederation of Indian Industry [CII], 2024)। व्यापार युद्ध से उत्पन्न कोई भी आपूर्ति श्रृंखला बाधा भारत के दवा उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** भारत में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की असेंबली में तेजी आई है, लेकिन डिस्प्ले पैनल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs), और मेमोरी चिप्स जैसे लगभग 80-85% घटक अभी भी चीन से आयात किए जाते हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सौर सेल और मॉड्यूल का एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है।

यह अत्यधिक निर्भरता भारत को दोहरे जोखिम में डालती है। पहला, चीन भू-राजनीतिक तनाव के समय इन आपूर्तियों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, आपूर्ति में किसी भी बाधा या चीन द्वारा कीमतों में वृद्धि से भारत में उत्पादन लागत बढ़ सकती है, जिससे **आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation)** का खतरा पैदा हो सकता है, जो अंततः भारतीय उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा।

3.3 अन्य विकासशील देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा : "चाइना प्लस वन" रणनीति से उत्पन्न होने वाले अवसरों के लिए भारत एकमात्र दावेदार नहीं है। वास्तव में, कई अन्य देश इस दौड़ में भारत से आगे निकलने की क्षमता रखते हैं। **वियतनाम, मेक्सिको, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड** जैसे देश भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

इन देशों के पास भारत की तुलना में कुछ विशिष्ट लाभ हैं। उदाहरण के लिए:

- **वियतनाम** के पास बेहतर बंदरगाह अवसंरचना, स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और RCEP जैसे प्रमुख व्यापार समझौतों की सदस्यता है, जो इसे कई बाजारों में शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करती है।

- **मेक्सिको** अपनी भौगोलिक निकटता और USMCA (यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट) के कारण अमेरिकी बाजार में आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है।
- **बांग्लादेश** ने रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र में अपनी वैश्विक प्रभुत्व स्थापित कर लिया है।

इन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में, भारत को अभी भी लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत, जटिल नियामक प्रक्रियाओं, और भूमि अधिग्रहण एवं श्रम कानूनों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (Boston Consulting Group [BCG], 2024)। जब तक भारत इन संरचनात्मक बाधाओं को दूर नहीं करता, तब तक वह विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने की अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा।

4. भू-राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ (Geopolitical & Strategic Implications) : अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रकटीकरण है जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ताने-बाने को बदल दिया है। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में, भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। भारत को न केवल अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी है, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए एक अस्थिर दुनिया में अपना स्थान भी सुरक्षित करना है।

4.1 रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण (Multi-Alignment) : शीत युद्ध के दौर की गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) की अपनी ऐतिहासिक नीति से विकसित होते हुए, भारत ने 21वीं सदी में **"बहु-संरेखण" (Multi-Alignment)** या **"मुद्दे-आधारित संरेखण" (Issue-based Alignment)** की एक अधिक व्यावहारिक और गतिशील रणनीति अपनाई है। इसका सार यह है कि भारत किसी एक शक्ति गुट के प्रति प्रतिबद्ध हुए बिना, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न देशों और समूहों के साथ सहयोग करेगा। अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता ने इस नीति को और भी प्रासंगिक बना दिया है (Raja Mohan, 2023)।

यह संतुलन भारत के कार्यों में स्पष्ट दिखता है:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ:** भारत ने अमेरिका के साथ अपनी **"वैश्विक रणनीतिक साझेदारी"** को लगातार गहरा किया है। इसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों की खरीद, BECA और COMCASA जैसे मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर, और मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं। यह साझेदारी चीन की बढ़ती मुखरता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने की साझा चिंता पर आधारित है।
- **चीन के साथ:** सीमा पर लगातार तनाव (जिसका सबसे गंभीर उदाहरण 2020 का गलवान संघर्ष था) के बावजूद, भारत ने चीन के साथ संचार के चैनल खुले रखे हैं। दोनों देश **ब्रिक्स (BRICS)** और **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सदस्य हैं। भारत का दृष्टिकोण टकराव को प्रबंधित करने और जहाँ संभव हो, व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने का है, जबकि अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर दृढ़ता से कायम है।

इस दोहरी नीति का उद्देश्य भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)** को संरक्षित करना है - यानी, किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव के बिना अपने विदेश नीति निर्णय लेने की क्षमता। यह एक जटिल संतुलनकारी कार्य है जो भारत की कूटनीति की निरंतर परीक्षा लेता है।

4.2 QUAD और इंडो-पैसिफिक में भारत की भूमिका : अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा ने **इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific)** को वैश्विक भू-राजनीति के केंद्रीय मंच के रूप में स्थापित कर दिया है। इस क्षेत्र में, **चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue - Quad)**, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। हालाँकि इसके सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि यह एक सैन्य गठबंधन नहीं है, इसे व्यापक रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के एक समूह

के रूप में देखा जाता है (Lowy Institute, 2024)।

क्वाड का एजेंडा अब पारंपरिक सुरक्षा से कहीं आगे निकल गया है। 2025 तक, इसके सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

- **महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियाँ:** 5G, AI और सेमीकंडक्टर के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाना।
- **अवसंरचना विकास:** चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के एक पारदर्शी और टिकाऊ विकल्प के रूप में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना।
- **समुद्री सुरक्षा:** एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य:** भविष्य की महामारियों का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन साझेदारी और स्वास्थ्य सुरक्षा पर सहयोग।

अपनी विशाल तटरेखा और हिंद महासागर में केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण, भारत क्वाड की सफलता के लिए अपरिहार्य है। भारत इस क्षेत्र में एक **"शुद्ध सुरक्षा प्रदाता" (Net Security Provider)** के रूप में अपनी भूमिका को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है, जो इसकी बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं और क्षेत्रीय प्रभाव को दर्शाता है (Ministry of External Affairs, India, 2024)।

4.3 पड़ोसियों के साथ संबंधों पर प्रभाव : अमेरिका-चीन की प्रतिद्वंद्विता दक्षिण एशिया में भी तीव्रता से महसूस की जा रही है, जिससे भारत के पड़ोस में एक नई "ग्रेट गेम" की स्थिति बन गई है। चीन ने अपनी **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के माध्यम से पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में बंदरगाहों, राजमार्गों और ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश करके अपना प्रभाव काफी बढ़ाया है। पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है।

चीन की इस बढ़ती उपस्थिति ने भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं, जिसमें "ऋण-जाल कूटनीति" (debt-trap diplomacy) और भारत को उसके अपने पड़ोस में घेरने की चिंताएँ शामिल हैं (Stobdan, 2024)। इसके जवाब में, भारत ने अपनी **"पड़ोसी पहले" (Neighbourhood First)** और **"सागर" (SAGAR - Security and Growth for All in the Region)** नीतियों को दोगुना कर दिया है। भारत अपने पड़ोसियों को विकास सहायता, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और सुरक्षा सहयोग के एक विश्वसनीय और पारदर्शी विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। श्रीलंका के हालिया आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा प्रदान की गई त्वरित और व्यापक सहायता इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में भारत की साख को मजबूत किया।

5. भारत की प्रतिक्रिया और भविष्य की रणनीति (India's Response and Future Strategy) : अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध द्वारा उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों के जवाब में, भारत ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। यह रणनीति न केवल तात्कालिक जोखिमों को कम करने पर केंद्रित है, बल्कि भारत को एक नई वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए स्थापित करने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी रखती है। इस प्रतिक्रिया के मुख्य स्तंभ 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान, व्यापार समझौतों के प्रति एक नया दृष्टिकोण, और आवश्यक घरेलू सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना है।

5.1 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का रणनीतिक विश्लेषण : 2020 में शुरू किया गया 'आत्मनिर्भर भारत' (Self-Reliant India) अभियान, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और चीन पर रणनीतिक निर्भरता की कमजोरियों के प्रति भारत की सीधी प्रतिक्रिया है। इसे संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाव के रूप में देखना एक भूल होगी; इसके

बजाय, इसे रणनीतिक क्षमता निर्माण की एक व्यापक पहल के रूप में समझा जाना चाहिए (NCAER, 2024)। इस अभियान के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

1. **रणनीतिक निर्भरता कम करना:** इसका प्राथमिक लक्ष्य फार्मास्यूटिकल्स (APIs), इलेक्ट्रॉनिक्स (सेमीकंडक्टर), दूरसंचार उपकरण और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन पर भारत की निर्भरता को व्यवस्थित रूप से कम करना है। यह भारत की आर्थिक संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य कदम माना जाता है।
2. **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण:** आत्मनिर्भरता का दूसरा पहलू भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को इतना मजबूत करना है कि यह दुनिया के लिए एक विश्वसनीय, लचीला और प्रतिस्पर्धी आपूर्ति केंद्र बन सके। **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI)** योजनाएं इसी उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, जो घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती हैं ताकि वे न केवल भारतीय बाजार की सेवा कर सकें, बल्कि यहाँ से निर्यात भी कर सकें (Government of India, 2020)।

हालांकि, इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, न कि अक्षम घरेलू उद्योगों को संरक्षण दे। इसके लिए निरंतर निगरानी और नीतिगत समायोजन की आवश्यकता होगी।

5.2 व्यापार समझौतों की समीक्षा: बहुपक्षवाद से द्विपक्षवाद की ओर : व्यापार युद्ध के संदर्भ में, भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के प्रति अपने दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 में **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)** में शामिल न होने का निर्णय था। यह निर्णय इस चिंता पर आधारित था कि चीन से आने वाले सस्ते आयात भारतीय बाजार पर हावी हो जाएंगे, जिससे घरेलू उत्पादकों और किसानों को नुकसान होगा (Ministry of Commerce and Industry, 2019)। 2025 तक के घटनाक्रमों को देखते हुए, यह निर्णय भारत को व्यापार युद्ध के सीधे प्रभावों से बचाने में दूरदर्शी साबित हुआ है।

RCEP जैसे बड़े बहुपक्षीय समझौतों से दूर रहते हुए, भारत अब **द्विपक्षीय FTAs** पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो उसकी विशिष्ट आर्थिक शक्तियों और कमजोरियों के अनुरूप हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में संपन्न हुए समझौते इस नई रणनीति की सफलता के प्रमाण हैं। वर्तमान में, भारत यूनाइटेड किंगडम (UK) और यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापक व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। यह दृष्टिकोण भारत को उन बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है जहाँ उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता अधिक है, जबकि वह अपने संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा भी कर सकता है (Jaishankar, 2024)।

5.3 आगे की राह: अपरिहार्य घरेलू सुधार : अंततः, भारत की वैश्विक अवसरों को भुनाने की क्षमता उसकी आंतरिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करती है। सरकार की नीतियां और वैश्विक रुझान केवल एक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं; वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए गहरे संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। भविष्य की रणनीति के लिए निम्नलिखित क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं:

- **लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** जैसी पहलों के बावजूद, भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत अभी भी कई प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अधिक है। बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के आधुनिकीकरण में तेजी लाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- **भूमि और श्रम सुधार:** ये भारत में निवेश के लिए लंबे समय से चली आ रही बाधाएं हैं। हालांकि केंद्र और कुछ राज्यों ने श्रम संहिताओं को लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं का सरलीकरण अभी भी एक बड़ी चुनौती है।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:** विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत की छलांग सराहनीय है, लेकिन जमीनी स्तर पर,

विशेष रूप से अनुबंध प्रवर्तन, संपत्ति पंजीकरण और विभिन्न अनुमतियों को प्राप्त करने में अभी भी कई बाधाएं हैं (NITI Aayog, 2025)। न्यायिक और प्रशासनिक सुधार इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

- **कौशल विकास:** उन्नत विनिर्माण और उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कार्यबल के कौशल का उन्नयन करना अत्यंत आवश्यक है।

संक्षेप में, भारत की भविष्य की रणनीति केवल बाहरी अवसरों पर प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी आंतरिक शक्तियों का निर्माण करने की होनी चाहिए ताकि वह वैश्विक मंच पर एक अग्रणी भूमिका निभा सके।

6. निष्कर्ष (Conclusion) : अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, जो एक आर्थिक विवाद के रूप में शुरू हुआ था, वर्ष 2025 तक एक व्यापक भू-राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है जो वैश्विक व्यवस्था को मौलिक रूप से नया आकार दे रहा है। यह शोध पत्र इस संघर्ष को भारत के दृष्टिकोण से विश्लेषित करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह टकराव भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो अपने साथ अभूतपूर्व अवसर और गंभीर चुनौतियाँ दोनों लेकर आया है। यह भारत के लिए केवल एक बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक उत्प्रेरक है जो उसकी आर्थिक नीतियों, विदेश नीति और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को फिर से परिभाषित कर रहा है।

जैसा कि इस पत्र में दर्शाया गया है, भारत के लिए आर्थिक अवसर स्पष्ट हैं। "चाइना प्लस वन" की वैश्विक प्रवृत्ति ने भारत को विनिर्माण और निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरने का अवसर दिया है, जिसे सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और PLI जैसी नीतियों से बल मिला है। इसने निर्यात बाजारों में भी नई संभावनाएं खोली हैं। हालांकि, इन अवसरों के साथ गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन पर आयात निर्भरता की कमजोरी, और वियतनाम तथा मेक्सिको जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा ऐसे जोखिम हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

रणनीतिक मोर्चे पर, भारत ने इस जटिल माहौल में अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए "बहु-संरक्षण" की एक कुशल नीति अपनाई है। एक ओर, वह अमेरिका और क्वाड के अन्य भागीदारों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा कर रहा है ताकि एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी ओर, वह चीन के साथ संवाद के रास्ते खुले रखता है और ब्रिक्स जैसे मंचों पर उसके साथ संलग्न रहता है, ताकि टकराव को प्रबंधित किया जा सके। यह संतुलनकारी कार्य भारत की बढ़ती कूटनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है।

अंततः, भारत की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि अमेरिका और चीन क्या करते हैं, बल्कि इस पर कि भारत स्वयं क्या करता है। वैश्विक अवसर केवल एक खिड़की प्रदान करते हैं; उस खिड़की से प्रवेश करने के लिए आवश्यक ताकत आंतरिक सुधारों से ही आएगी। लॉजिस्टिक्स, श्रम, भूमि और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों को लागू करने की भारत की क्षमता ही यह निर्धारित करेगी कि वह इस भू-राजनीतिक पुनर्संरक्षण का कितना लाभ उठा पाता है।

संक्षेप में, अमेरिका-चीन संघर्ष ने भारत को वैश्विक मंच के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह एक आरामदायक स्थिति नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा अवसर है जो एक पीढ़ी में एक बार आता है। सही रणनीतिक दृष्टि और साहसिक घरेलू सुधारों के साथ, भारत इस अनिश्चितता के दौर से न केवल सुरक्षित निकल सकता है, बल्कि 21वीं सदी की एक **अग्रणी शक्ति (Leading Power)** के रूप में अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकता है। आने वाले वर्ष निःसंदेह भारत के संकल्प और अनुकूलन क्षमता की परीक्षा लेंगे, और इस दशक में लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके भविष्य की दिशा तय करेंगे।

संदर्भ सूची (Bibliography) :

1. Boston Consulting Group. (2024). The Shifting Landscape of Global Manufacturing: Choosing the Right Location (pp. 14-22). BCG Publications.
2. Center for Strategic and International Studies. (2024). The New Tech Cold War: Semiconductors and the Future of Global Power (pp. 34-45). CSIS Press.
3. Confederation of Indian Industry. (2024). De-risking India's Supply Chains: The Imperative of Reducing Dependency on China in Key Sectors (pp. 9-15). CII National Council.
4. Federation of Indian Export Organisations. (2025). Annual Report on India's Foreign Trade (pp. 56-63). FIEO.
5. Financial Times. (2025, August 30). US expands tariff regime beyond China, hitting key allies. Financial Times, p. A4.
6. Government of India. (2020). AatmaNirbhar Bharat Abhiyan: Policy Document. Press Information Bureau.
7. International Monetary Fund. (2025). World Economic Outlook: Navigating a Fragmented Global Economy (pp. 27-38). IMF Publications.
8. Jaishankar, S. (2024). The India Way: Strategies for an Uncertain World (2nd Ed.). HarperCollins India.
9. Kissinger, H. (2014). World Order. Penguin Books.
10. Lowy Institute. (2024). The Quad 2.0: Balancing Ambition and Reality in the Indo-Pacific (pp. 7-18).
11. Mearsheimer, J. J. (2021). The Inevitable Rivalry: America, China, and the Tragedy of Great Power Politics. Foreign Affairs, 100(6), 48-58.
12. Ministry of Commerce and Industry, Government of India. (2019, November 4). Prime Minister's Statement at the RCEP Summit in Bangkok. Press Release.
13. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. (2025). Impact Assessment of the Production-Linked Incentive (PLI) Scheme for Large-Scale Electronics Manufacturing (pp. 21-29).
14. Ministry of External Affairs, Government of India. (2024). Annual Report 2023-24 (pp. 88-95).
15. National Council of Applied Economic Research (NCAER). (2024). Evaluating 'Self-Reliance': A Mid-Term Analysis of the Atmanirbhar Bharat Initiative (pp. 41-53). NCAER Press.
16. NITI Aayog. (2024). Realizing the Vision of a Self-Reliant India: The Role of PLI Schemes (pp. 11-19). Government of India.

17. NITI Aayog. (2025). Strategy for New India @ 75: A Progress Report and Path Forward (pp. 112-120). Government of India.
18. Peterson Institute for International Economics. (2024). Trade Diversion: The Unintended Consequences of the U.S.-China Trade War (pp. 5-12). PIIE Press.
19. Raja Mohan, C. (2023). India's Balancing Act: Navigating the New World Disorder. Penguin Random House India.
20. Reserve Bank of India. (2025). Annual Report on Foreign Direct Investment in India (pp. 72-78). RBI Publications.
21. Stobdan, P. (2024). The New Great Game in South Asia: China's BRI and India's Response. Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA).
22. The Economist Intelligence Unit. (2024). Global Risk Report: Geopolitical Tensions and Investment Climates (pp. 6-11). EIU.
23. United States Trade Representative. (2019). Findings of the Investigation into China's Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation Under Section 301 of the Trade Act of 1974 (pp. 101-115). USTR.
24. World Bank. (2023). Global Value Chain Development Report 2023: Resilient and Sustainable GVCs in the Wake of COVID-19 (pp. 45-57). World Bank Publications.
25. World Trade Organization. (2023). Global Value Chain Development Report 2023: De-risking, Not Decoupling (pp. 33-41). WTO Publications.

•